मै/स सहकारी खंड उद्योग मंडल लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त

9 मार्च, 2005

(रूमा पाल, अरिजीत पासायत और सी. के. ठक्कर, जे. जे.,)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, की पहली अनुसूची की मद संख्या 1 धारा 11 बी, छूट अधिसूचना नं. 257/76 और 108/78

छूट अधिसूचना-पिछले तीन वर्षों में औसत उत्पादन से अधिक चीनी के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाने से छूट-धनवापसी दावा-माना छूट का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी को कुछ निर्धारित अनुपात में निर्धारित अवधि के दौरान बेचा जाता है। लेकिन निर्धारिती ने इसे अलग-अलग अनुपात में बेचा- राजस्व ने अधिसूचना के अनुरूप धनवापसी राशि की सही गणना की थी- हालाँकि, दावा समय सीमा से वर्जित है।

"अन्यायपूर्ण संवर्धन" का सिद्धान्त-लागू- मानाः वह साम्यता के आधार पर लागू है- चूंकि निर्धारिती ने उपभोक्ताओं से राशि पूर्व में ही वसूल कर ली है, अगर अब यदि वसूली की अनुमति दी जाती है तो इसकी परिणिति "अन्यापूर्ण संर्वधन" होगा।

अपीलकर्ता-चीनी के निर्माता, निर्धारिती ने छूट अधिसूचना संख्या 257/76 के आधार पर छूट का दावा किया था। अधिसूचना में पिछले तीन वर्षों के लिए चीनी के औसत उत्पादन से अधिक उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट का प्रावधान है। राजस्व ने पाया कि निर्धारिती ने अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुपात और अधिसूचना के तहत लाभ का दावा करने की आवश्यकताओं में से एक से भिन्न अनुपात में लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी बेची थी । इस कारण अधिसूचना के अनुरूप दावे को कम कर दिया और यह भी पाया कि निर्धारिती पहले ही ग्राहकों से शुल्क राशि एकत्र कर चुके थे, इसलिए वे राशि का दावा करने के हकदार नहीं थे। इसलिए यह राशि ग्राहक कल्याण कोष में हस्तांतरित कर दी गई। अपीलीय प्राधिकरण और न्यायाधिकरण ने भी आदेश की पुष्टि की। अतः यह वर्तमान अपीलें।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

मानाः 1.1. अपीलार्थी-निर्धारिती किसी भी राहत का हकदार नहीं है। परिसीमा के आधार पर, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि दावा वर्ष 1976-77 के उत्पादन के संबंध में था। निर्धारिती को 31 मार्च, 1978 तक दावा दायर करना चाहिए था। लेकिन दावा 14 अगस्त, 1978 को प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, इसे परिसीमा द्वारा वर्जित माना जाना उचित था। हालांकि, संबंधित अपील में तीन वर्षों के लिए चीनी के औसत उत्पादन के संबंध में, प्रत्यर्थी का तर्क अच्छी तरह से स्थापित है कि दो साल के औसत उत्पादन पर अधिसूचना संख्या 108/78 के संदर्भ में विचार किया जाना था।

सिद्धेश्वर सहकारी सखार कारखाना लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य 1999 की सिविल अपील सं. 5866 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 23 फरवरी, 2005 का आधार लिया गया।

1.2. दोनों अधिसूचनाएँ बहुत स्पष्ट हैं। इसका लाभ उक्त अधिसूचनाओं के तहत छूट के लाभ का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब चीनी 65:35 क्रमशः लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी के अनुपात में बेची जाती है। चूंकि निर्धारिती 65:35 की छूट के लाभ का दावा कर रहा था, निर्धारिती द्वारा अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट अनुपात में चीनी बेचना अनिवार्य था और जब तक वह शर्त पूरी नहीं होती, तब तक उसके द्वारा शुल्क से छूट के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता था। निर्धारिती द्वारा वास्तविक बिक्री के आधार पर, राजस्व ने उत्पाद शुल्क से छूट की राशि की गणना की थी जो अधिसूचनाओं के अनुरूप थी और निर्धारिती द्वारा उस निर्णय के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जा सकती है।

2.1. ''अन्यायपूर्ण संवर्धन'' का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी लाभ को बनाए रखना जो अन्यायपूर्ण या असमान है। 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' तब होता है जब कोई व्यक्ति धन या लाभ रखता है जो न्याय, समानता और अच्छे विवेक में किसी और के हैं। 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' का सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर असमान रूप से समृद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वसूली का अधिकार'

के सिद्धांत के तहत उत्पन्न होता है जहां किसी लाभ को बनाए रखना न्याय के विपरीत या समानता के खिलाफ माना जाता है।

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य। (1977) 5 एससीसी 536: (1997) 99 ई. एल. टी. 247; भारत संघ बनाम जैन स्पिनर्स लिमिटेड, (1992), 4 एस. सी. सी. 389 और भारत संघ बनाम आई. टी. सी. लिमिटेड, (1993), सप्लीमेंट्री 4 एस. सी. सी. 326, को आधार बनाया गया।

हिंदुस्तान मेटल प्रेसिंग वर्क्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे, {2003}, 3 एससीसी 559, विशिष्ट।

2.2. 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' का सिद्धांत साम्यता पर आधारित है और कई मामलों में स्वीकार और लागू किया गया। इसलिए, प्रयोज्यता की परवाह किए बिना अधिनियम की धारा 11बी के अनुसार, इस सिद्धांत का उपयोग उस लाभ से इनकार करने के लिए किया जा सकता है जिसका व्यक्ति अन्यथा हकदार नहीं है। अधिनियम की धारा 11 बी या इसी तरह की प्रावधान केवल इस सिद्धांत को विधायी मान्यता देता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वैधानिक प्रावधान के अभाव में, एक व्यक्ति अनुचित लाभ बनाए रखने का दावा कर सकता है। धनवापसी की राहत का दावा करने से पहले, याचिकाकर्ता/निर्धारिती के लिए यह दिखाना आवश्यक है कि उसने उस राशि का भुगतान कर दिया है जिसके लिए राहत मांगी गई है और यदि ऐसी राहत नहीं दी जाती है, तो उसे नुकसान होगा।

गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट पिटीशन स 567/94 में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2005 को निर्णीत का अनुसरण किया गया।

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, {1977}, 5 एससीसी 536 (1997) 99 ई. एल. टी. 247; हिंदुस्तान मेटल प्रेसिंग वर्क्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे, {2003} 3 एस. सी. सी. 559; नवाबगंज शुगर मिल्स कं. लिमिटेड बनाम भारत संघ, {1976}, 1 एस. सी. सी. 120 {1976}, 1 एससीआर 803, मै0 शिव शंकर दाल मिल्स बनाम हरियाणा राज्य, {1980}, 2 एस. सी. सी. 437; ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उडीसा राज्य, {1962}, 1 एस. सी. आर. 549 और अमर नाथ ओम प्रकाश और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, {1985}, 1 एससीसी 345:{1985} 2 एस. सी. आर. 72, पर भरोसा किया।

मुलमचंद बनाम मध्यप्रदेश राज्य ए. आई. आर. (1968) एस. सी. 1218, संदर्भित।

फाइब्रोसा बनाम फेयरबेर्न, {1942} 2 ऑल ई. आर. 122 और नेल्सन बनाम लारहोल्ट, {1947}, 2 ऑल ई. आर. 751, संदर्भित।

3. सभी निम्न अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलार्थी ने उपभोक्ताओं से राशि वसूल कर ली है और इस प्रकार उत्पाद शुल्क उपभोक्ताओं/ग्राहकों को दे दिया जाता है। विशिष्ट निष्कर्ष को

देखते हुए, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि निर्धारिती किसी भी राशि का दावा करने का हकदार नहीं है। छूट या राशि की वापसी की अनुमति देने से निर्धारिती द्वारा 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' होगा जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, उस हिसाब से भी, अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों और लाभ देने से इनकार को मनमाना, अनुचित या असमान नहीं माना जा सकता है।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1999 की सिविल अपील सं. 6832 और 6833।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 1.6.99/6.7.99 दिनांकित निर्णय और आदेश से, सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय पीठः एफ0 ओ0 सं0 सी-आई/1482-1483/ डब्ल्यू जेड बी/1999 ए0 सं0 ई-704 और 717 _ 1994 - बम्बई।

अपीलार्थी की ओर से रमेश सिंह, प्रताप वेणुगोपाल, पी. एस. सुधेर और अमित सिंह के0 जे0 जोन की ओर से ।

प्रत्यथी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. सरन और अनुव्रत शर्मा बी कृष्ण प्रसाद की ओर से।

न्यायालय का निर्णय ठक्कर जे. द्वारा दिया गया था

ये दोनों अपीलें 1 जून, 1999 को सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, पश्चिमी क्षेत्रीय पीठ, बॉम्बे (इसके बाद' ') द्वारा पारित एक सामान्य आदेश

से उत्पन्न हुई, जिसके द्वारा सहायक कलेक्टर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वलसाड द्वारा मूल रूप से पारित आदेशों की पुष्टि की गई है जिसकी संपुष्टि केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), अहमदाबाद के कलेक्टर द्वारा की गई।

वर्तमान अपीलों में पक्षों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर विचार करने से पहले, दोनों मामलों के प्रासंगिक तथ्यों को संक्षेप में बताया जा सकता है। 1999 की सिविल अपील संख्या 6832 मेसर्स सहकारी खंड उद्योग मंडल लिमिटेड (संक्षेप में 'मंडल')द्वारा दायर की गई है मंडल के अनुसार, यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की पहली अनुसूची के आइटम नंबर 1 के उप आइटम (1) के अंतर्गत आने वाली चीनी के निर्माण में लगा हुआ है । अपीलकर्ता-मंडल ने रेंज वन अधिकारी, बिलीमोरा को संबोधित अपने पत्र दिनांक 14 अगस्त, 1978 के माध्यम से रुपये 6,92,779.59 पैसे की छूट का दावा किया। रिफंड का दावा 30 सितंबर 1976 की अधिसूचना संख्या 257/76 के आधार पर किया गया था। अधिसूचना सरकार द्वारा केंद्र के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी। उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित)। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि में चीनी के औसत उत्पादन से अधिक पर लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि

ऐसी छूट लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी के रूप में कॉलम 3 और 4 में निर्दिष्ट चीनी की बिक्री पर होगी।

अपीलकर्ता-मंडल के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान मंडल द्वारा चीनी का उत्पादन इस प्रकार थाः

1973-74 - 1,68,636 क्विंटल

1974-75 - 1,65,308 क्विंटल

1975-76 - 1,30,595 क्विंटल

इस प्रकार तीन वर्षों का कुल उत्पादन 4,64,539 क्विंटल हुआ। 1973-74, 1974-75 और 1975-76 की अवधि के लिए तीन वर्षों का औसत उत्पादन 1,54,846.33 क्विंटल (4,64,539 - 3) था। चूँकि वर्ष 1976-77 में चीनी का उत्पादन 2,09,982 क्विंटल था, अपीलकर्ता-मंडल 55,135.67 क्विंटल के अतिरिक्त उत्पादन के लिए चुंगी शुल्क से छूट का लाभ पाने का हकदार था। इसलिए, अपीलकर्ता ने रुपये 6,92,779.59 पैसे के लिए अपना दावा प्रस्तुत किया।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर ने 29 मार्च, 1993 के एक आदेश द्वारा, दावे को अधिनियम की धारा 11बी के तहत कालातीत माना क्योंकि यह छह महीने के बाद दायर किया गया था। उन्होंने यह भी माना कि 1,348.80 रुपये की राशि के लिए, दावेदार 48 किलोग्राम चीनी से संबंधित दावे का हकदार नहीं था। जो पुनः संसाधित चीनी थी और इसलिए स्वीकार्य नहीं है। 6,92,779.59 रुपये की राशि के संबंध में, सहायक

कलेक्टर ने कहा कि छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, अतिरिक्त चीनी को क्रमशः 65:35 के अनुपात में लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी के रूप में बेचा जाना था। अपीलकर्ता ने निम्नानुसार राशि का दावा कियाः

क्रं. सं.	अतिरिक्त उत्पादन	प्रतिशत का अनुपात	चीनी का प्रकार	प्रति क्विंटल की दर	कुल छूट
1	55135.67	65.00%जो जो 35838.18	लेवी	4.2	1,50,520.40
2	55135.67	35.00%जो जो 19297.48	फ्री सेल	28.1	5,42,259.19
कुल					रू 6,92,779.59

अपीलकर्ता द्वारा वास्तविक बिक्री के बाद, यह पाया गया कि 55,135.67 क्विंटल चीनी के अतिरिक्त उत्पादन में से, मंडल ने लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी के रूप में चीनी इस प्रकार बेची थीः

42133 क्विंटल. लेवी चीनी x रु.4.20 = 1,76,1958.60

(छूट की दर)

13003 क्विंटल निःशुल्क बिक्री x रु. 28.10 = 3,65,384.30

चीनी (छूट की दर)

कुल = रु.5,40,342.90

इसलिए, सहायक कलेक्टर के अनुसार, दावेदार 6,92,779.59 रुपये का दावा नहीं कर सकता था, बल्कि केवल 5,42.342.90 रुपये का दावा कर सकता था। सहायक कलेक्टर ने आगे देखा कि दावेदार ने पहले ही अपने ग्राहकों से शुल्क राशि वसूल और एकत्र कर ली थी और इस तरह वह उक्त राशि का दावा करने का हकदार नहीं था। इसलिए, उन्होंने यह राशि भारत सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष में अंतरित कर दी।

सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), अहमदाबाद के कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की। अपीलकर्ता प्राधिकारी के समक्ष, यह तर्क दिया गया था कि सहायक कलेक्टर ने दावे को समय से बाधित मानकर कानूनी त्रुटि की है; 1,348.80 रुपये के दावे को कम करने में निर्णायक प्राधिकारी की ओर से एक त्रुटि इस आधार पर हुई थी कि चीनी पुनः संसाधित माल थी और कोई छूट नहीं दी जा सकती थी और लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी के 65:35 के अनुपात को सही ढंग से लागू नहीं किया गया था और सहायक कलेक्टर को दावा कम नहीं करना चाहिए था . उन्होंने मंडल को राशि का भुगतान न करके भी गलती की। चूंकि सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश

कानून के विपरीत था, इसलिए प्रतिवादियों को अपीलकर्ता - मंडल द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का आदेश देकर इसे रद्द किया जाना चाहिए था।

अपीलीय प्राधिकारी ने 1,348.80 रुपये के दावे के संबंध में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। और यह देखते हुए इसे बरकरार रखा कि अधिसूचना संख्या 257/76 के अनुसार, दावेदार उक्त राशि का हकदार था और दावे को अस्वीकार करने का आदेश उचित नहीं था और तदनुसार इसे रद्द कर दिया गया था। दावे को सीमा से बाधित किए जाने के संबंध में, यह देखा गया कि चूंकि चीनी वर्ष 30 सितंबर, 1976 को समाप्त हो गया था, इसलिए दावा छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। लेकिन दावा 14 अगस्त, 1978 को प्रस्तुत किया गया था, और इसलिए, यह परिसीमा द्वारा बाधित था। मंडल द्वारा यह तर्क दिया गया कि शुरू में दावेदार ने 1976 की अधिसूचना संख्या 36 के लाभ का दावा किया था, लेकिन चीनी निदेशालय द्वारा 19 जुलाई, 1978 को दावेदार को सूचित करने के बाद कि मंडल का दावा खारिज होने योग्य था, उसने वर्तमान दावा 14 अगस्त, 1978 को दायर किया। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकारी ने पाया कि सहायक कलेक्टर कानून के प्रावधान से आगे नहीं जा सकते थे और जब अधिनियम की धारा 11 बी के तहत समय सीमा निर्धारित की गई थी, तो दावे को समय बाधित सही माना गया था।

दावेदार को राशि का भुगतान न करने के संबंध में, अपीलीय प्राधिकारी ने पाया कि सहायक कलेक्टर ने रिफंड का उपभोक्ता कल्याण कोष में अतंरण सही किया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दावेदार ने अधिनियम की धारा 11 बी के तहत अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत को लागू करने पर आपत्ति जताई और तर्क दिया कि छूट कारखानों को अधिक चीनी के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन की प्रकृति में थी और ऐसी छूट का उद्देश्य उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना नहीं था । लेकिन यह देखा गया कि धारा 11बी में संशोधन के साथ, नया प्रावधान संशोधन से पहले दायर किए गए दावों सहित सभी दावों पर लागू होगा। कलेक्टर ने यह भी पाया कि अधिसूचना संख्या 257/76 में ''छूट'' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसमें संलग्न तालिका में निर्दिष्ट दर पर लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी पर शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 11बी की उपधारा (2) के तहत आवेदक को कुछ मामलों में उत्पाद शुल्क की वापसी का प्रावधान है। चूंकि हस्तगत मामला उक्त प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता था क्योंकि मंडल ने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया था, इसलिए मंडल को ऐसी राशि नहीं मिल सकी। इसलिए, उन्होंने अपीलें खारिज कर दीं।

पीड़ित अपीलकर्ता ने सी ई जी ए टी से संपर्क किया। सी ई जी ए टी के समक्ष भी, निचले प्राधिकारियों के समक्ष दिए गए तर्कों को दोहराया गया। हालाँकि, सी ई जी ए टी ने सहायक कलेक्टर के साथ-साथ कलेक्टर

द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। सी ई जी ए टी के अनुसार, दावा ''स्पष्ट रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित'' था। सी ई जी ए टी ने यह भी देखा कि भले ही दावा सीमा से बाधित नहीं था, यह इस न्यायालय के फैसले मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (1977), 5 एससीसी 536:(1997) 99 ईएलटी 247 के फैसले के अंतर्गत आएगा तदनुसार अपील खारिज कर दी गई।

1999 की सिविल अपील संख्या 6833 में, अपीलकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 1 सितंबर, 1978 के माध्यम से रेंज वन अधिकारी, बिलीमोरा को 6,44,841 रूपये की छूट का दावा दर्ज कराया। छूट का दावा अधिसूचना संख्या 108/78 दिनांक 28 अप्रैल, 1978 के आधार पर किया गया था। उक्त अधिसूचना के तहत, एक चीनी कारखाना पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि के चीनी के अतिरिक्त उत्पादन पर उत्पाद शुल्क से छूट का हकदार था। अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी छूट लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी के रूप में कॉलम (3) और (4) में निर्दिष्ट चीनी की बिक्री पर होगी। मंडल के अनुसार, अपीलकर्ता मंडल द्वारा पिछले तीन वर्षों में चीनी का उत्पादन इस प्रकार थाः

1975 - 15,573 क्विंटल

1976 - शून्य

1977 - 24,817 क्विंटल

कुल - 40,390 क्विंटल

1978 - 45,845 क्विंटल।

अपीलकर्ता के अनुसार, पहले तीन वर्षों का औसत 13,466.67 क्विंटल आया और इसलिए अपीलकर्ता 32,378.33 क्विंटल के अतिरिक्त उत्पादन पर छूट का हकदार था। हालाँकि, प्राधिकरण ने माना कि चूंकि सरकार की नीति के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा एक वर्ष (1976) के लिए चीनी का 'शून्य उत्पादन किया गया था, इसलिए उक्त वर्ष को नजरअंदाज करना आवश्यक था। इन परिस्थितियों में, प्राधिकरण ने माना कि अपीलकर्ता का औसत उत्पादन 20,195 क्विंटल (40,390 - 2) था। उस आधार पर, अपीलकर्ता 25,650 क्विंटल के अतिरिक्त उत्पादन पर छूट का दावा करने का हकदार था। सहायक कलेक्टर ने यह भी देखा कि लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी का अनुपात 65:35 बनाए रखना होगा।

अपीलकर्ता को निम्नानुसार चीनी बेचनी चाहिए थीः

16672.50 क्विं.x रु. 9.60 = रु. 1,60,056.00

8,977.50 क्वि. x रु.54.00 = रु. 4,84,785.00

कुल रु. = 6,44,841.00

हालांकि, अपीलकर्ता ने लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी को निम्नलिखित अनुपात में मंजूरी दे दीः

21,261 क्वि.. x रु. 9.60 = रु. 2,04,105.60

4,389 क्वि. x रु. 54.00 = रु. 2,37,006.00

कुल = रु. 4,41,111.60

इसलिए, अपीलकर्ता 6,44,841 रुपये का दावा नहीं कर सका, बल्कि केवल 4,41,111.60 रुपये का दावा कर सका। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीनी फैक्ट्री ने उन ग्राहकों से शुल्क राशि ''पहले ही' चार्ज और एकत्र कर ली है, जिन्हें मुफ्त बिक्री चीनी के साथ-साथ लेवी चीनी जारी की गई है'', सहायक कलेक्टर ने कहा कि अधिनियम की धारा 11 बी के तहत, मंडल सरकार से उक्त राशि का दावा नहीं कर सके। उन्होंने इन परिस्थितियों में दावा घटाकर 4,44,111.60 रुपये कर दिया, लेकिन राशि को भारत सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष में अंतरित कर दिया।

सहायक कलेक्टर द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने अपील दायर की लेकिन सीमा शुल्क कलेक्टर द्वारा अपील खारिज कर दी गई। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पीड़ित अपीलकर्ता ने सी ई जी ए टी मे संपर्क किया। सी ई जी ए टी ने भी अपील खारिज कर दी। दोनों मामलों में सी ई जी ए टी द्वारा पारित समान आदेश को मंडल द्वारा वर्तमान अपीलों में चुनौती दी गई है।

हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। अपीलकर्ता-मंडल के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि निचले प्राधिकारियों ने अपीलकर्ता के दावे को कालबाधित मानकर कानूनी त्रुटि की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिकारी 28 अप्रैल, 1978 की अधिसूचना संख्या 108/78 की अनुचित

व्याख्या करके और उक्त अधिसूचना के अनुसार औसत उत्पादन की गणना करके 1999 की सिविल अपील संख्या 6833 में अपीलकर्ता के दावे को कम करने में गलत थे। विद्वान वकील के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा तीन वर्षों में चीनी का उत्पादन इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि एक वर्ष के लिए कोई उत्पादन नहीं हुआ था, तीन वर्षों में विभाजित किया जाना आवश्यक था। उस मामले में अपीलकर्ता 32,378.33 क्विंटल के अतिरिक्त उत्पादन का लाभ पाने का हकदार होगा, न कि 25,650 क्विंटल का। वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अन्यायपूर्ण संवर्धन के सिद्धांत के आवेदन पर अधिकारियों का निर्णय अनुचित और गलत था और मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में निर्धारित अनुपात लागू नहीं होगा। वकील के अनुसार, अधिकारियों द्वारा धारा 11बी की उपधारा (2) को लागू नहीं किया जा सकता था और अपीलकर्ता दावे के अनुसार छूट का हकदार था। यह तर्क दिया गया कि छूट देने का उद्देश्य चीनी कारखानों को अधिक से अधिक चीनी उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना था और इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को नहीं बल्कि कारखानों को देना था। इसलिए, अधिकारियों के लिए अपीलकर्ता को राहत देने से इनकार करने के लिए बाहरी आधार पर विचार करना संभव नहीं था। इसलिए यह राशि भारत सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष में नहीं भेजी जा सकती थी, बल्कि दावेदार को दी जानी चाहिए थी। वकील ने यह भी कहा कि लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी के लिए निर्धारित कोटा पर चीनी की वास्तविक बिक्री के आधार पर अपीलकर्ता के दावे को कम करने में अधिकारियों की ओर से एक त्रुटि हुई

थी। चीनी सरकार की नीति के अनुसार बेची गई, अतः छूट कम करना अनुचित था। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि दोनों अपीलों को उचित निर्देश के साथ अनुमति देते हुए उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता-मंडल को राशि का भुगतान करने के उचित निर्देश दिए जाने चाहिए।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन किया। उनके अनुसार, एक दावा स्पष्ट रूप से परिसीमा से बाधित था। यह तथ्य दर्ज किया गया है कि दावा छह महीने की अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, दावे को खारिज करने में अधिकारी सही थे। औसत उत्पादन के संबंध में, वकील ने कहा कि अधिसूचना संख्या 108/78 का खंड 3 स्पष्ट है और इसमें कहा गया है कि पिछले तीन चीनी वर्षों की अवधि के लिए औसत उत्पादन की गणना की जाएगी, जिसमें कारखाने ने उक्त अवधि के दौरान वास्तव में काम किया है। . जिस अवधि तक इसने काम नहीं किया उसे नजरअंदाज करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि औसत की गणना सरकार की नीति और अधिसूचना के खंड 3 के अनुसार थी और ऐसी कार्रवाई के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जा सकती। गुण-दोष के आधार पर, वकील ने तर्क दिया कि चीनी के अतिरिक्त उत्पादन की छूट के लाभ का दावा करने के लिए, चीनी की बिक्री सरकार की लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी की नीति के अनुसार होनी चाहिए। रिकॉर्ड से, यह स्पष्ट है और अधिकारियों द्वारा एक निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि चीनी की बिक्री लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी के

लिए क्रमशः 65: 35 के अनुपात में नहीं थी और इसलिए, लाभ की गणना वास्तविक चीनी की बिक्री के आधार पर की गई थी और कार्रवाई कानूनी, वैध और उचित थी। चुंगी शुल्क से छूट की राशि को उपभोक्ता कल्याण कोष में अंतरित करने की अपीलकर्ता की शिकायत के संबंध में, यह तर्क दिया गया कि बेशक अपीलकर्ता को कोई नुकसान नहीं हुआ है। चुंगी राशि ग्राहकों को दे दी गई है और अपीलकर्ता द्वारा पहले ही वसूल कर ली गई है। इसलिए, अधिनियम की धारा 11बी की उपधारा (2) के तहत , मंडल ऐसी राशि का दावा नहीं कर सकता। लेकिन भले ही यह मान लिया जाए कि धारा 11बी का सामान्य सिद्धांत पर कोई उपयोग नही है तो भी, अपीलकर्ता को ऐसी राशि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' होगी। इसलिए, उक्त लाभ न देकर, अधिकारियों ने कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है। इस कारण, उन्होंने कहा कि अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं।

पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारी राय में, अपीलकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है। परिसीमा के संबधं में रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि 1999 की सिविल अपील संख्या 6832 में दावा वर्ष 1976-77 के उत्पादन के संबंध में था। यह 30 सितंबर, 1977 तक के दावे से संबंधित है और अपीलकर्ता को छह महीने के भीतर यानी 31 मार्च, 1978 को या उससे पहले दावा दायर करना चाहिए था। स्वीकृत रूप से

दावा 14 अगस्त, 1978 को प्रस्तुत किया गया था। इसलिए, यह सीमा से वर्जित सही माना जाता है।

1999 की सिविल अपील संख्या 6833 में तीन वर्षों के लिए चीनी के औसत उत्पादन के संबंध में, हमारी राय में, प्रतिवादी के विद्वान वकील की दलील अच्छी तरह से स्थापित है कि दो वर्षों के औसत उत्पादन पर विचार किया जाना चाहिए। 28 अप्रैल 1978 की अधिसूचना संख्या 108/78 का खंड 3 इस प्रकार हैः

> "3. जहां उक्त तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित अवधि के दौरान पिछले तीन चीनी वर्षों में से किसी में उत्पादन शून्य था, औसत उत्पादन निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगाः -
>
> पिछले तीन चीनी वर्षों में उक्त अवधि के लिए औसत उत्पादन की गणना उस अवधि या अवधियों के आधार पर की जाएगी जिसमें कारखाने ने वास्तव में उक्त अवधि के दौरान काम किया था और वह अवधि या अवधियो जिसमें उसने उक्त अवधि के दौरान काम नहीं किया था की अवधि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।"

इसी तरह का एक प्रश्न हाल ही में दिनाकं 23 फरवरी 2005 को निर्णीत सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य, सिविल अपील संख्या 5866, 1999 में हमारे सामने विचार के लिए

आया था। उस मामले में भी, अपीलकर्ता कारखाना ने एक वर्ष तक कोई चीनी का उत्पादन नहीं किया। इसलिए, अधिकारियों ने कारखाने के औसत उत्पादन की गणना करते समय उक्त वर्ष को नजरअंदाज कर दिया। कारखाना द्वारा एक शिकायत की गई थी कि प्राधिकरण की कार्रवाई अवैध थी और चीनी के उत्पादन को एक वर्ष तक गैर-उत्पादन को नजरअंदाज करते हुए तीन वर्षों में विभाजित किया जाना चाहिए था। अधिसूचना और उसके खंड 3 में इस्तेमाल की गई भाषा की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने इस विवाद को खारिज कर दिया और माना कि जब एक वर्ष तक कारखाना में तब कोई उत्पादन नहीं हुआ था उक्त अवधि को नजरअंदाज करना आवश्यक था और सरकार द्वारा इसे उचित रूप से नजरअंदाज किया गया। हमारी राय में, उक्त मामले में निर्धारित अनुपात मौजूदा मामले पर भी लागू होता है और प्रतिवादी की कार्रवाई को अवैध या कानून के विपरीत नहीं ठहराया जा सकता है।

तब यह तर्क दिया गया कि लेवी चीनी की बिक्री और मुफ्त बिक्री चीनी के आधार पर छूट की मात्रा कम करने में अधिकारी सही नहीं थे। अपीलकर्ता-मंडल के अनुसार, मंडल द्वारा चीनी बेची गई थी, अधिकारियों को इस तथ्य से अवगत कराया गया था, और कुछ भी नहीं छुपाया गया था। जब अधिकारियों को पता था और फिर भी उनके द्वारा किसी भी समय कोई आपत्ति नहीं ली गई, तो इस आधार पर राशि कम करना उनके लिए खुला नहीं था कि अपीलकर्ता मंडल द्वारा लेवी चीनी की बिक्री 65 प्रतिशत

और मुफ्त बिक्री चीनी 35 प्रतिशत सरकार की तथाकथित नीति के अनुसार नहीं थी। उस आधार पर राशि में कटौती अवैध और गैरकानूनी थी।

हम तर्क को कायम रखने में असमर्थ हैं. हमारी राय में, दोनों अधिसूचनाएँ बिल्कुल स्पष्ट हैं। उक्त अधिसूचनाओं के तहत लाभ का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब चीनी क्रमशः 65:35 लेवी चीनी और मुफ्त बिक्री चीनी के अनुपात में बेची जाती है। चूंकि अपीलकर्ता उत्पाद शुल्क से छूट के लाभ का दावा कर रहा था, इसलिए अपीलकर्ता-मंडल के लिए अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट 65:35 के अनुपात में चीनी बेचना अनिवार्य था और जब तक वह शर्त पूरी नहीं होती, तब तक शुल्क से छूट की लाभ का दावा नहीं किया जा सकता था। अपीलकर्ता द्वारा वास्तविक बिक्री के आधार पर, प्रतिवादी ने उत्पाद शुल्क से छूट की राशि की गणना की थी जो अधिसूचनाओं के अनुरूप थी और अपीलकर्ता द्वारा उस निर्णय के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की जा सकती थी।

यह भी तर्क दिया गया कि निचले प्राधिकारी अधिसूचनाओं के लाभ से इनकार करने के लिए अधिनियम की धारा 11बी के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकते थे । 1978 के संशोधन अधिनियम (1978 का अधिनियम 25) द्वारा 17 नवंबर 1980 से धारा 11बी को अधिनियम में शामिल किया गया था। इसमें अतिरिक्त भुगतान के कुछ मामलों में कर्तव्यों की वापसी

का प्रावधान था। इस धारा को 19 सितंबर, 1991 से संशोधन अधिनियम 1991 (1991 का अधिनियम 14) द्वारा और संशोधित किया गया था ।

यूनियन ओफ इंड़िया बनाम जैन स्पिनर लिमिटेड (1992), 4 एससीसी 389 और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम आईटीसी लिमिटेड, (1993), सप्लीमेंट 4 एससीसी 326 में, इस न्यायालय ने माना कि जब तक रिफंड की कार्यवाही लंबित है और अंतिम रूप नही दिए जाने पर, संशोधित प्रावधान आकर्षित हो जाते हैं और निर्माता को संशोधित प्रावधानों के विपरीत किसी भी रिफंड का दावा करने से वंचित किया जा सकता है। इसे अलग ढंग से कहें तो, 1991 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित धारा 11 बी के प्रावधान लंबित रिफंड के दावों पर भी लागू होंगे। यह माना गया कि न्यायालय रिफंड को नियंत्रित करने वाले कानून में बदलाव पर ध्यान देने के लिए बाध्य है और निर्माता को यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि जिस उत्पाद शुल्क की राशि के संबंध में रिफंड का दावा किया गया था, वह उसके द्वारा ग्राहकों को नहीं दी गई थी।

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, इस न्यायालय ने जैन स्पिनर्स लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड में निर्धारित कानून को दोहराया। बहुमत के लिए बोलते हुए, बीपी जीवन रेड्डी, जज ने माना कि न्यायालय को अधिनियम में साक्ष्य के विधायी इरादे का उचित सम्मान करना चाहिए। और कानून के प्रावधानों के अनुरूप क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना चाहिए।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हिंदुस्तान मेटल प्रेसिंग वर्क्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पुणे , (2003), 3 एससीसी 559 में इस न्यायालय के फैसले का हवाला दिया और कहा कि अधिनियम की धारा 11बी में निहित सिद्धांत अतीत के मामलों पर लागू नहीं होंगे। हालाँकि, यह कहा जा सकता है कि उस मामले में, कार्यवाही को अंतिम रूप दिया गया था, लेनदेन समाप्त हो गया था और राशि 1989 में निर्धारिती को वापस कर दी गई थी। उस तथ्य-स्थिति में, इस न्यायालय ने माना कि पिछले पूर्ण संव्यवहार को इस आधार पर फिर से नहीं खोला जा सकता है वह रिफंड गलती से दिया गया था और अन्यायपूर्ण संवर्धन हुआ था। वर्तमान मामले में तथ्य-स्थिति बिल्कुल अलग है। राशि उपभोक्ताओं को दे दी गई है और मंडल द्वारा राशि वापस करने का दावा किया गया है। इसलिए, हिंदुस्तान मेटल प्रेसिंग वर्क्स में निर्धारित अनुपात अपीलकर्ता को मदद नहीं करता है।

अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं है। इसलिए, उक्त सिद्धांत को अधिकारियों द्वारा उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट के लाभ से इनकार करने और उस राशि का भुगतान करने से इनकार करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है जिसके लिए अपीलकर्ता को हकदार माना गया था और इसे सरकार द्वारा उपभोक्ता कल्याण कोष द्वारा स्थापित किया गया था।

हम उस तर्क से भी प्रभावित नहीं हैं. हमारे विचार में, प्रस्तुत तर्क का कोई आधार नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सीधे तौर पर कहा जाए तो, 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लाभ को अपने पास रखना जो अन्यायपूर्ण या असमान है। 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' तब होता है जब कोई व्यक्ति धन या लाभ अपने पास रखता है जो न्याय, समानता और अच्छे विवेक के आधार पर किसी और का होता है।

इसलिए, 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' का सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर असमान रूप से समृद्ध होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' के सिद्धांत के तहत वसूली का अधिकार तब उत्पन्न होता है जब किसी लाभ को बनाए रखना न्याय के विपरीत या समानता के विरुद्ध माना जाता है।

दायित्व का न्यायिक आधार किसी अनुबंध या अपकृत्य पर आधारित नहीं है, बल्कि कानून की तीसरी श्रेणी, अर्थात् अर्ध-अनुबंध या पुनर्स्थापन के सिद्धांत पर आधारित है।

फाइब्रोसा बनाम फेयरबैर्न, (1942), 2 ऑल ई आर 122 के प्रमुख मामले में, लॉर्ड राइट ने सिद्धांत को इस प्रकार बतायाः

> "...(ए) कानून की कोई भी सभ्य प्रणाली उन मामलों के लिए उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य है जिन्हें अन्यायपूर्ण संवर्धन या अन्यायपूर्ण लाभ कहा गया है, यानी

किसी व्यक्ति को दूसरे के धन को बनाए रखने या उससे प्राप्त कुछ लाभ को रोकने के लिए जो कि उसके विवेक जिसे उसे रखना चाहिए के विरूद्ध है। अंग्रेजी कानून में ऐसे उपचार अनुबंध या अपकृत्य में उपचार से सामान्य रूप से भिन्न होते हैं, और अब उन्हें सामान्य कानून की तीसरी श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है जिसे अर्ध-अनुबंध या पुनर्स्थापन कहा गया है। ''

लॉर्ड डेनिंग ने नेल्सन बनाम लारहोल्ट,(1947) 2 ऑल ई आर 751 में भी कहा था;

''हालाँकि, कानून और समानता के बीच अंतर करना अब उचित नहीं है। सिद्धांतों को अब उनके संयुक्त प्रभाव के प्रकाश में बताया जाना चाहिए। न ही कार्रवाई के पुराने रूपों की बारीकियों को समझाना आवश्यक है। उपचार अब निर्भर करते हैं अधिकार के सार पर, न कि इस बात पर कि क्या उन्हें किसी विशेष ढांचे में फिट किया जा सकता है। यहां अधिकार इक्विटी या अनुबंध या अपकृत्य के लिए विशिष्ट नहीं है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उन मामलों की महत्वपूर्ण श्रेणी में आता है जहां अदालत क्षतिपूर्ति का आदेश देती है यदि न्यायिक मामले की यह आवश्यकता है।''

उपरोक्त सिद्धांत भारत में स्वीकार कर लिया गया है। इस न्यायालय ने कई मामलों में 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' के सिद्धांत को लागू किया है।

ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य,(1962),1 एससीआर 549 में, इस न्यायालय ने एक डीलर को रिफंड नहीं दिया क्योंकि वह पहले ही खरीदार पर बोझ डाल चुका था। यह देखा गया कि विधानमंडल के लिए यह प्रावधान करना खुला था कि व्यक्तियों द्वारा भुगतान की गई अवैध कर की राशि का दावा केवल उनके द्वारा किया जा सकता है, डीलर द्वारा नहीं और डीलर के रिफंड प्राप्त करने के अधिकार पर ऐसा प्रतिबंध कानूनी रूप से आम जनता के हित में लगाया जा सकता हैं।

मूलमचंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य में एआईआर (1968) एससी 1218 में, वन उपज को हटाने के लिए वादी और सरकार के बीच एक अनुबंध किया गया था। वादी ने 10,000 रुपये की राशि जमा की और वन उपज एकत्र की। हालाँकि, यह पता चला कि संविधान के अनुच्छेद 299 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था और अनुबंध शून्य था। वादी ने 10,000 रुपये की वापसी का दावा किया।

अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 70 के प्रावधान को लागू करते हुए और फाइब्रोसा और नेल्सन का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने कहाः

"...यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जो व्यक्ति मुआवजा चाहता है, उसका यह कर्तव्य है कि वह वादी द्वारा

लेखांकन में प्राप्त की गई राशि का प्रतिवादी को हिसाब दे, जो प्रतिवादी से मुआवजे की एक शर्त है'।

अमर नाथ ओम प्रकाश और अन्य। बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (1985), 1 एससीसी 345: (1985) 2 एससीआर 72, पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 की धारा 23ए ने बाजार समितियों को लाइसेंसधारियों से उनके द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए उद्ग्रहणीय राशि से अधिक शुल्क को बनाए रखने में सक्षम बनाया, यदि लाइसेंसधारियों द्वारा ऐसी फीस का बोझ क्रेताओं पर डाला गया हो। उक्त प्रावधान की वैधता को चुनौती दी गई और रिफंड का दावा किया गया। हालाँकि, न्यायालय ने ओरिएंट पेपर मिल्स पर भरोसा करते हुए माना कि उपभोक्ता जनता जिसने अंतिम बोझ उठाया था, वे वास्तव में धन वापसी के हकदार थे और चूंकि बाजार समितियाँ उनके हितों का प्रतिनिधित्व करती थीं, वे राशि और लाइसेंसधारियों को बनाए रखने के हकदार थे जिन्होंने शुल्क लगाया था और उपभोक्ताओं से वसूली गई राशि लाभ का दावा नहीं कर सके।

कोर्ट ने कहाः

> " धारा 23-ए का प्राथमिक उद्देश्य स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है; यह बाजार समिति द्वारा डीलरों को लाइसेंस शुल्क की वापसी को रोकता है, जो पहले से ही इस तरह के शुल्क का बोझ कृषि उपज के अगले खरीदार पर डाल चुके

हैं और जो बाजार समिति से रिफंड प्राप्त करके अन्यायपूर्ण तरीके से खुद को समृद्ध करना चाहते हैं, धारा 23-ए, वास्तव में, उपभोक्ता-जनता को मान्यता देती है जिन्होंने अंतिम बोझ वहन किया है, जिन्होंने वास्तव में राशि का भुगतान किया है और इसलिए वे किसी भी अतिरिक्त शुल्क के रिफंड के हकदार हैं। और इसलिए राशि को बनाए रखने के लिए उनके हित का प्रतिनिधित्व करने वाली बाजार समिति को निर्देश दिया जाता है। इसे इस रूप में होना चाहिए क्योंकि व्यवहार में, उन व्यक्तिगत खरीदारों और उपभोक्ताओं का पता लगाने का प्रयास करना एक कठिन और निरर्थक अभ्यास होगा जिन्होने अंततः बोझ वहन किया है। यह वास्तव में जनता को वह लौटाने वाला कानून है जो उसने जनता से लिया है, समिति को अधिनियम के तहत आवश्यक सेवाओं के प्रदर्शन के लिए राशि का उपयोग करने में सक्षम बनाकर। बिचैलियों को गलत तरीके से लाभ कमाने की अनुमति देने के बजाय, विधायिका ने अत्यधिक लेवी द्वारा किए गए गलत काम को पूर्ववत करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की है, जिससे समितियों को उन लोगों के लाभ के लिए उपयोग की जाने वाली राशि को बनाए रखने की अनुमति मिलती है जिनके लाभ के लिए विपणन कानून अधिनियमित किया गया था।''

इस न्यायालय ने माना कि प्रावधान ने बाजार समितियों के माध्यम से जनता को वह दिया जो उन्होंने जनता से लिया था और उसका हक था। इसने सीजर को वही प्रदान किया जो सीजर का था।

ओरिएंट पेपर मिल्स लिमिटेड और अमर नाथ ओम प्रकाश में निर्धारित कानून को मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

शिव शंकर दाल मिल्स बनाम हरियाणा राज्य, (1980), 2 एससीसी 437, में बाजार शुल्क एक प्रावधान के तहत एकत्र किया गया था जिसे इस न्यायालय ने पहले के मामले में रद्द कर दिया था। इसलिए, व्यापारियों द्वारा उनसे एकत्र की गई राशि वापस करने की प्रार्थना की गई। इस न्यायालय ने माना कि यद्यपि व्यापारियों से बाजार शुल्क की वसूली अवैध थी, लेकिन व्यापारी केवल उसी राशि की मांग कर सकते थे जो ग्राहकों को नहीं दी गई थी। उस दृष्टिकोण के लिए, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति की विवेकाधीन प्रकृति का भी उल्लेख किया। नवाबगंज शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, (1976), 1 एससीसी 120: (1976) 1 एससीआर 803 के बाद, न्यायालय ने उन लोगों को राशि वापस करने के लिए एक योजना तैयार की, जिनसे व्यापारियों द्वारा अवैध संग्रह किया गया था।

मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भी, इस न्यायालय ने माना कि गलत तरीके से भुगतान किए गए कर/शुल्क की वापसी का दावा इक्विटी के सिद्धांत के आधार पर किया जा सकता है और ऐसी क्षतिपूर्ति की मांग करने वाले व्यक्ति को अभिवचित करना होगा और साबित करना होगा कि उसने ऐसे कर/शुल्क का भुगतान किया था और उसे चोट/नुकसान हुआ था। यह साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर है कि उसके द्वारा भुगतान किया गया करध्शुल्क ग्राहकों या तीसरे पक्ष को नहीं दिया गया है और वह क्षतिपूर्ति का हकदार है।

सविधान पीठ के हाल ही के फैसले गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य रिट याचिका से 567/1994 दिनांक 20 जनवरी 2005 के मामले का भी संदर्भ दिया जा सकता है। उस मामले में, उत्तर प्रदेश विलासिता कर अधिनियम, 1995 के साथ-साथ अन्य राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता को राज्य विधानमंडल द्वारा विधायी क्षमता के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने याचिका स्वीकार कर ली और माना कि राज्य विधानमंडल तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर विलासिता कर लगाने में सक्षम नहीं है और अधिनियमों को अधिकारातीत और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। हालाँकि, बीच की अवधि में, अपीलकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं से कर एकत्र किया गया और राज्य सरकार को भी भुगतान किया गया। कुछ मामलों में, अपीलकर्ताओं द्वारा कर की वसूली के खिलाफ इस न्यायालय से अंतरिम

राहत प्राप्त की गई थी और जैसा कि राज्य सरकार ने आरोप लगाया था, अपीलकर्ताओं ने उपभोक्ताओं/ग्राहकों से कर वसूलना जारी रखा।

इन परिस्थितियों में, संविधान पीठ के माध्यम से बोलते हुए, हम में से एक, (रूमा पाल, जे.) ने कहा;

> " सोमालिया ऑर्गेनिक्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम यूपी राज्य (2001), 5 एससीसी 519, के सिद्धान्तों का पालन करते हुए विवादित अधिनियमों को रद्द करते समय हम विवादित अधिनियम के तहत पहले से भुगतान किए गए करों की किसी भी वापसी की अनुमति देना उचित नहीं समझते हैं। यदि निर्धारिती द्वारा कोई बैंक गारंटी दी गई है तो वह समाप्त समझी जाएगी।
>
> राज्य सरकारों की ओर से कहा गया कि विलासिता कर की वसूली के खिलाफ इस न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ताओं ने उपभोक्ताओं/ग्राहकों से ऐसे कर वसूलना जारी रखा। आरोप है कि उन्होंने संबंधित राज्य सरकारों को ऐसा कर नहीं चुकाया। इसलिए, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि अपीलकर्ताओं को उपभोक्ताओं से विलासिता कर के रूप में एकत्र की गई राशि को अपने पास रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह उनके द्वारा "अन्यायपूर्ण संवर्धन" होगा।

हमारी राय में, प्रस्तुत तर्क अच्छी तरह से स्थापित है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। यदि अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय से अंतरिम आदेश प्राप्त करने के बाद उपभोक्ताओं/ग्राहकों से विलासिता कर की कोई राशि एकत्र की है, तो वे संबंधित राज्य सरकारों को उक्त राशि का भुगतान करेंगे।''

उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि 'अन्यायपूर्ण संवर्धन' का सिद्धांत समानता पर आधारित है और इसे कई मामलों में स्वीकार और लागू किया गया है। इसलिए, हमारी राय में, अधिनियम की धारा 11 बी की प्रयोज्यता के बावजूद, सिद्धांत को उस लाभ से इनकार करने के लिए लागू किया जा सकता है जिसके लिए कोई व्यक्ति अन्यथा हकदार नहीं है। अधिनियम की धारा 11 बी या इसी तरह का प्रावधान केवल इस सिद्धांत को विधायी मान्यता देता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि वैधानिक प्रावधान के अभाव में, कोई व्यक्ति अनुचित लाभ का दावा कर सकता है या उसे बरकरार रख सकता है। रिफंड की राहत का दावा करने से पहले, याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता को यह दिखाना आवश्यक है कि उसने उस राशि का भुगतान कर दिया है जिसके लिए राहत मांगी गई है, उसने इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला है और यदि ऐसी राहत नहीं दी गई, तो उसे नुकसान होगा।

वर्तमान मामले में, न केवल अपीलकर्ता-मंडल द्वारा ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया है, बल्कि स्थिति बिल्कुल विपरीत है। सभी निचले प्राधिकारियों ने स्पष्ट रूप से एक निष्कर्ष दर्ज किया है कि अपीलकर्ता-मंडल ने उपभोक्ताओं से राशि की वसूली की है और इस तरह उत्पाद शुल्क उपभोक्ताओं/ग्राहकों को दिया गया है। विशिष्ट निष्कर्ष के मद्देनजर, हमारी राय में, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि अपीलकर्ता-मंडल किसी भी राशि का दावा करने का हकदार नहीं है। छूट की अनुमति देने या राशि की वापसी के परिणामस्वरूप अपीलकर्ता को 'अनुचित संवर्धन' होगा जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए, हमारी राय में, उस आधार पर भी, प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश और लाभ देने से इनकार को मनमाना, अनुचित या असमान नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, उक्त आधार को भी खारिज किया जाना चाहिए।

उपरोक्त कारणों से, दोनों अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जाएगा। अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेखा वधवा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।